भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2896
(दिनांक 05.08.2026 को उत्तर के लिए)

मिशन कर्मयोगी और एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण डिजिटल क्षमता निर्माण

2896. श्री लुम्बाराम चौधरी:
डॉ. के. सुधाकर:
श्री बलभद्र माझी:
डॉ. संजय जायसवाल:
सुश्री बाँसुरी स्वराज:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूमिका-आधारित मानव संसाधन ढांचे को अपनाने की दिशा में 'मिशन कर्मयोगी' के अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं और एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईजीओटी) प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी है और जारी किए गए पाठ्यक्रम प्रमाण पत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ओडिशा के नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सेवारत सरकारी कर्मचारी उक्त पहल से लाभान्वित हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यक्तिगत शिक्षण, दक्षता मानचित्रण और सामग्री अनुशंसाओं के लिए, विशेषकर ओडिशा के नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सेवारत अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने हेतु, आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है;

(घ) डिजिटल रिपॉजिटरी में प्रमुख भारतीय भाषाओं को शामिल करने की वर्तमान स्थिति क्या है और ओडिशा के नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यशील विभागों सहित विभिन्न सरकारी विभागों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्षमता-निर्माण के परिणामों को सरकारी कर्मचारियों की करियर प्रगति और प्रदर्शन मूल्यांकन के साथ एकीकृत करने के लिए अपनाए गए ढांचे का ब्यौरा क्या है और ओडिशा के नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यशील कार्यालयों और विभागों में इसका कितना कार्यान्वयन हुआ है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ) : भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) को सितंबर, 2020 में अनुमोदन प्रदान किया गया था जिसका लक्ष्य 'नियम आधारित' से 'भूमिका आधारित' मानव संसाधन प्रणालियों को अपनाना तथा भारतीय लोक व्यवहार से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण के साथ सिविल सेवक तैयार करना था।

राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम-मिशन कर्मयोगी के अधीन स्थापित आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के परिमाण और पहुंच में निरंतर तेजी से विस्तार हो रहा है। संघ सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस प्लेटफॉर्म पर शामिल किए जा चुके हैं। क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) के साथ स्पेशल पर्पज व्हीकल-कर्मयोगी भारत (केबी) ने मिशन कर्मयोगी के चरणबद्ध कार्यान्वयन हेतु 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज की तिथि के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर 1.70 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत प्रयोक्ता हैं और इस पर कार्यक्षेत्र, कार्यात्मक और व्यवहारात्मक दक्षताओं पर 5600 से ज्यादा पाठ्यक्रम उपलब्ध है। ये पाठ्यक्रम अंग्रेजी और हिंदी सहित 23 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, जो इसे व्यापक रूप से सुगम्य बनाने और क्षेत्रीय तथा भाषायी जरूरतों के साथ जोड़ने में समर्थ बनाता है। आईगॉट पोर्टल पर अब तक 14.29 से ज्यादा पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।

पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और उभरती प्रौद्योगिकियों पर 218 पाठ्यक्रम हैं, जिन्हें सरकारी अधिकारियों को मूलभूत डिजिटल ज्ञान और कौशल से सुसज्जित कराने हेतु डिजाइन किया गया है। इन पाठ्यक्रमों में शिक्षा और कौशल, कार्यालयी उत्पादकता, कृषि, जन-स्वास्थ्य, एआई सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन पाठ्यक्रमों के लिए 7.3 करोड़ से ज्यादा नामांकन और 3.35 करोड़ से ज्यादा पाठ्यक्रम पूर्णता दर्ज की गई है।

एआई को व्यक्तिगत अधिगमता (लर्निंग), दक्षता मैपिंग और पाठ्यक्रम अनुशंसाओं के साथ सम्मिलित करने की दृष्टि से, आईगॉट एआई ट्यूटर, आईगॉट एआई सारथी, और एआई-सीबीपी टूल जैसी विशेषताएं शुरू की गई हैं। एआई के उपयोग के साथ, सभी पाठ्यक्रमों के लिए उपशीर्षक और लिप्यंतर (ट्रांसक्रिप्ट) भी 11 प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवाएं जा रहे हैं।

रिपोर्टिंग वर्ष 2025-26 से, केंद्र सरकार के सभी कार्मिकों और अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) के अधिकारियों द्वारा वार्षिक रूप से आईगॉट पर निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाना अपेक्षित है जो उनकी वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (एपीएआर) में प्रदर्शित होगा, इस प्रकार यह क्षमता विकास को मानव संसाधन प्रबंधन से जोड़ेगा।

इस पोर्टल में जिला-वार सूचना प्रदर्शित नहीं होती है। तथापि, ओडिशा राज्य के अधिकारी/कार्मिक सक्रिय रूप से आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल का उपयोग कर अपनी क्षमता विकास कौशल को बढ़ा रहे हैं। योजना के चरणबद्ध कार्यान्वयन हेतु ओडिशा राज्य, केबी और सीबीसी के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आज की तिथि तक, इस पोर्टल पर ओडिशा सरकार के 4,31,725 अधिकारी/कार्मिक शामिल हैं और इस पर कुल 31,72,167 पाठ्यक्रम पूर्णता दर्ज की गई है। आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सभी पाठ्यक्रम केंद्रीय रूप से ऑनलाइन उपलब्ध (होस्ट) कराए जाते हैं और किसी भी स्थान से प्लेटफॉर्म में शामिल सभी सरकारी कार्मिकों के लिए समान रूप से अधिगम्य है।

*****